जागृति

वर्ष.65 अंक-5 मुंबई अप्रैल, 2021

पीएमईजीपी के तहत कार्य कर रही महिला उद्यमी, माननीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री से पुरस्कार प्राप्त करते हुए

केवीआईसी ने हनी मिशन के तहत कर्नाटक में 100 साल पुरानी कूर्ग की शहद गतिविधियों को पुनर्जीवित किया

खादी और ग्रामोद्योग आयोग की औद्योगिकीकरण विषयक मासिक पत्रिका

खादी और ग्रामोद्योग आयोग

जागृति

खादी और ग्रामोद्योग आयोग की औद्योगिकीकरण विषयक मासिक पत्रिका

वर्ष 65 अंक-5 मुंबई अप्रैल-2021

सम्पादकीय मण्डल

अध्यक्ष
श्रीमती प्रीता वर्मा

संपादक
एम. राजन बाबू

सह संपादक
स्मिता जी. नायर

उप संपादक
सुबोध कुमार

अ.उप संपादक
शिव दयाल कुशवाहा

डिजाईन व पृष्ठसज्जा
सुबोध कुमार

प्रचार निदेशालय द्वारा
खादी और ग्रामोद्योग आयोग,
ग्रामोदय, 3 इर्ला रोड,
विले पार्ले (पश्चिम), मुंबई -400056
के लिए ई-प्रकाशित
ईमेल: editorialpublicitykvic@gmail.com
वेबसाइट: www.kvic.org.in

आवश्यक नहीं कि पत्रिका में प्रकाशित लेखों तथा विचारों से खादी और ग्रामोद्योग आयोग अथवा संपादक सहमत हों

इस अंक में.....

समाचार सार ..... 3 से 26

माननीय प्रधानमंत्री की बांग्लादेश यात्रा के दौरान खादी मुजीब जैकेट ने समारोहों की शोभा बढ़ायी .....

कोविड महामारी के बावजूद, केवीआईसी ने पीएमईजीपी के तहत अब तक का उच्चतम रोज़गार सृजन किया .....

केवीआईसी ने मधुमक्खियों का उपयोग करके हाथियों तथा मनुष्यों के बीच टकराव को रोकने के लिए री-हैब परियोजना की शुरुआत की ..

श्री नितिन गडकरी द्वारा स्फूर्ति योजना के तहत क्लस्टर्स स्थापित करने हेतु कार्यशाला का उद्घाटन .....

केवीआईसी ने हनी मिशन के तहत कूर्ग में कर्नाटक की 100 साल पुरानी हनी गतिविधियों को पुनर्जीवित किया .....

केवीआईसी के ऑनलाइन बिक्री पोर्टल ने नई ऊंचाइयों को छुआ; स्वदेशी को अधिक बढ़ावा .....

बांस उद्योग में 30,000 करोड़ रुपए तक बढ़ने की क्षमता: .....

एमएसएमई मंत्री द्वारा एमएसएमई के प्रौद्योगिकी केंद्रों,विस्तार केंद्रों और उद्यम एक्सप्रेस का उद्घाटन .....

आयोग ने कुम्हार सशक्तिकरण योजना के तहत राजस्थान में 11 जिलों के 1000 कुम्हार परिवारों को सशक्त बनाया .....

डीटीसी बस चालकों और परिचालकों को खादी फेस मास्क की आपूर्ति.....

आयोग मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया .....

डूंगरी, ओखलकांडा में स्फूर्ति योजना के तहत मधुमक्खीपालन पर एक दिवसीय जागरूकता शिविर का आयोजन .....

प्रयागराज माघ मेले में राज्य स्तरीय खादी प्रदर्शनी का आयोजन ...

आयोग, मुख्यालय, मुंबई में हिन्दी कार्यशाला आयोजित .....

प्रेस कवरेज 27-33

माननीय प्रधानमंत्री की बांग्लादेश यात्रा के दौरान खादी मुजीब जैकेट ने समारोह की शोभा बढ़ायी

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2021:भारत की विरासत के रूप में पहचानी जाने वाली खादी माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 26 और 27 मार्च को संपन्न हुई दो-दिवसीय बांग्लादेश यात्रा के दौरान सभी का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए तैयार थी। खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने खासतौर पर डिजाइन की गई 100 "मुजीब जैकेटों" की आपूर्ति की थी, जो प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान गणमान्य लोगों के द्वारा पहनी गयी।

"मुजीब जैकेट" बंगबंधु शेख मुजीब - उर - रहमान द्वारा पहने जाने वाले मुख्य परिधान के रूप में प्रसिद्ध है, जिन्हें बांग्लादेश का राष्ट्रपिता कहा जाता है। क्योंकि बांग्लादेश शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी पर "मुजीब बोरशो" मना रहा है, ढाका में भारतीय उच्चायोग के इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केन्द्र ने माननीय प्रधानमंत्री की यात्रा से पहले 100 मुजीब जैकेट का ऑर्डर दिया था।

विशेष रूप से डिजाइन की गई मुजीब जैकेट को हाथों से तैयार ऊंची गुणवत्ता वाली पॉलि खादी फैब्रिक से बनाया गया है। काली मुजीब जैकेट को 6 बटन, निचले हिस्से में दो जेब और सामने बायीं तरफ एक जेब के साथ डिजाइन किया गया, जैसे रहमान पहना करते थे। खादी वस्त्र की पर्यावरण अनुकूल प्रकृति की तर्ज पर इन जैकेट का कवर भी काले खादी कॉटन फैब्रिक से बनाया गया है, जिसके ऊपर खादी इंडिया का लोगो बना हुआ है। इन जैकेट को जयपुर में केवीआईसी के कुमारप्पा नेशनल हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट (केएनएचपीआई) में विशेष रूप से डिजाइन किए गए हाथ से बने प्लास्टिक मिश्रित पेपर कैरी बैग में ले जाया गया।

केवीआईसी के माननीय अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने कहा की "मुजीब जैकेट का बांग्लादेश में ऐतिहासिक महत्व है और यह बड़े गर्व की बात है कि खादी से बनी मुजीब जैकेट माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की बांग्लादेश यात्रा के दौरान पहनी गयी, जो खुद खादी के एक बड़े ब्रांड एंबेसडर हैं।"

श्री सक्सेना ने कहा कि "मुजीब जैकेट बांग्लादेश में खासा लोकप्रिय परिधान है। पुरानी पीढ़ी के लिए मुजीब जैकेट उनके महान नेता शेख मुजीब- उर - रहमान की विचारधारा का प्रतीक

शेष पृष्ठ ..... 06 पर

कोविड महामारी के बावजूद, केवीआईसी ने पीएमईजीपी के तहत अब तक का उच्चतम रोज़गार सृजन किया

एमएसएमई मंत्री श्री नितिन गडकरी ने प्रदर्शन पर खुशी जाहिर की

कोविड -19 महामारी के समय आर्थिक हताशा के बावजूद खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने एक साल में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत रोजगार सृजन में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दर्ज किया है। 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष 2020-21,जो देशव्यापी लॉकडाउन से काफी हद तक प्रभावित था के दौरान खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने पीएमईजीपी के तहत 2188.78 करोड़ रुपये खर्च कर 5,95,320 रोज़गारों का सृजन किया जो वर्ष 2008 में लॉन्च होने के बाद अब तक का उच्चतम स्तर है। केवीआईसी ने पूरे देश में 74,415 परियोजनाओं की स्थापना की। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम देश भर में रोजगार सृजन करने हेतु केंद्र सरकार की प्रमुख योजना है जिसके क्रियान्वयन के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग, एक स्वतंत्र अभिकरण (नोडल एजेंसी) है।

माननीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री, श्री नितिन गडकरी ने केवीआईसी की उपलब्धि की सराहना करते हुए कहा कि स्थानीय रोज़गार का सृजन लाखों लोगों की आजीविका प्रदान करने के साथ देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगा। यह उपलब्धि अधिक महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि सभी उत्पादन गतिविधियों, परिवहन और रसद लॉकडाउन के कारण 3 महीने से अधिक समय तक निलंबित रहे।

वर्ष 2020- 21 में, 2120. 81 करोड़ रुपये के लक्ष्य के सापेक्ष, केवीआईसी ने 2188.78 करोड़ रु मार्जिन मनी का वितरण किया जो लक्ष्य का 103.2 प्रतिशत है जो 2019-20 के दौरान संवितरित मार्जिन मनी से लगभग 12.19 प्रतिशत अधिक है। इसी तरह, नई परियोजनाओं और रोजगार सृजन की स्थापना में, KVIC ने लक्ष्य का 106.2% हासिल किया।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने रोजगार सृजन में इस ऊंची छलांग के लिए माननीय प्रधान मंत्री जी के "आत्मनिर्भर भारत" और "वोकल फॉर लोकल" तथा एमएसएमई मंत्री श्री नितिन गडकरी के निरंतर मार्गदर्शन और सहयोग को बताया।

श्री सक्सेना ने कहा "कोविड -19 महामारी के मद्देनजर सरकार के स्थानीय विनिर्माण और स्वरोजगार क्षेत्र पर ज़ोर ने यह अद्भुत कार्य किया है। पीएमईजीपी के तहत बड़ी संख्या में युवाओं, महिलाओं और समाज के कमजोर वर्गों के लोगों को स्वरोजगार गतिविधियों के लिए प्रेरित किया गया। इसके अलावा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय तथा खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा पीएमईजीपी के तहत परियोजनाओं के निष्पादन में तेजी लाने के लिए किए गए नीतिगत फैसलों की एक श्रृंखला ने केवीआईसी को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन प्राप्त करने में मदद की"।

जटिल कलेक्टरों की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय टास्क फोर्स कमेटी (डीएलटीएफसी) की भूमिका को पीएमईजीपी के तहत परियोजनाओं के समय पर और तेजी से क्रियान्वयन में अड़चन के रूप में देखा गया था क्योंकि अक्सर पाया गया था कि इस महत्वपूर्ण योजना को जिला कलेक्टरों द्वारा कम से कम प्राथमिकता दी गई। तदनुसार, एमएसएमई मंत्रालय ने 28 अप्रैल, 2020 को पीएमईजीपी परियोजनाओं

वर्ष	स्थापित परियोजनाओं की संख्या	मार्जिन मनी वितरित (रु.करोड़)	सृजित किये गए रोजगार
2020-21	74,415	2188.78	5,95,320
2019-20	66653	1950.83	5,33,224
2018-19	73,427	2070.00	5,87,416

शेष पृष्ठ सं .... 9 पर

केवीआईसी ने मधुमक्खियों का उपयोग करके हाथियों तथा मनुष्यों के बीच टकराव को रोकने के लिए री-हैब परियोजना की शुरुआत की

नई दिल्ली, 15मार्च, 2021:हाथियों के एक झुंड की कल्पना करें, जो सबसे बड़ा जानवर होता हैऔर समान रूप से बुद्धिमान भी, उन्हें शहद वाली छोटी-छोटी मधुमक्खियों के द्वारा मानव बस्ती से दूर भगाया जा रहा है। इसे अतिशयोक्ति कहा जा सकता है, लेकिन, यह कर्नाटक के जंगलों की एक वास्तविकता है।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने देश में मानव-हाथी टकरावको कम करने के लिए "मधुमक्खी-बाड़" बनाने की एक अनूठी परियोजना सोमवार कोशुरू की। प्रोजेक्ट री-हैब (मधुमक्खियों के माध्यम से हाथी-मानव हमलों को कम करनेकी परियोजना) का उद्देश्य शहद वाली मधुमक्खियों का उपयोग करके मानव बस्तियों में हाथियोंके हमलों को विफल करना है और इस प्रकार से मनुष्य व हाथी दोनों के जीवन की हानि कोकम से कम करना है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना द्वारा 15 मार्च, 2021 को कर्नाटक के कोडागु जिले के चेलूर गांव के आसपास चार स्थानों पर पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया। ये सभी स्थान नागरहोल नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व के बाहरी इलाकों में स्थित हैं और मानव-हाथी टकरावको रोकने के लिए कार्यरत है। री-हैब परियोजना की कुल लागत सिर्फ 15 लाख रुपये है।

प्रोजेक्ट री-हैब केवीआईसी के राष्ट्रीय शहद मिशन के तहत एक उप-मिशनहै। चूंकि शहद मिशन मधुवाटिका स्थापित करके मधुमक्खियों की संख्या बढ़ाने, शहद उत्पादनऔर मधुमक्खी पालकों की आय बढ़ाने का एक कार्यक्रम है, तो प्रोजेक्ट री-हैब हाथियों के हमले को रोकने के लिए मधुमक्खी के बक्से को बाड़ के रूप में उपयोग करता है।

केवीआईसी ने हाथियों के प्रवेश मार्ग को मानवीय आवासों के लिए अवरुद्ध करने में हाथी-मानव संघर्ष क्षेत्रों के मार्ग के सभी चार स्थानों में से प्रत्येक जगह पर मधुमक्खियों के 15-20 बॉक्स स्थापित किए हैं। बक्से एक तार के साथ जुड़े हुएहैं ताकि जब हाथी गुजरने का प्रयास करें, तब एक टग या पुल हाथी के झुंड को आगे बढ़नेसे रोक दे। मधुमक्खी के बक्से को जमीन

पर रखा गया है और साथ ही हाथियों के मार्ग कोअवरुद्ध करने के लिए पेड़ों से लटकाया गया है। हाथियों पर मधुमक्खियों के प्रभाव और इन क्षेत्रों में उनके व्यवहार को रिकॉर्ड करने के लिए रणनीतिक बिंदुओं पर किसी निष्कर्षपर पहुंचने के लिए नाइट विजन कैमरे लगाए गए हैं।

केवीआईसी के अध्यक्ष श्री सक्सेना ने मानव-हाथी टकराव को रोकने के लिए एक स्थायी संकल्प के रूप में इसे एक अनोखी पहल बताया और कहा कि यह समस्या देश के कई हिस्सों में आम बात है। उन्होंने कहा कि "यह वैज्ञानिक रूप से भी माना गया है कि हाथी, मधुमक्खियों से घबराते हैं और वे मधुमक्खियों से डरते भी हैं। हाथियों को डर रहता है कि, मधुमक्खी के झुंड सूंड और आंखों के उनके संवेदनशील अंदरुनी हिस्से को काटसकते हैं। मधुमक्खियों का सामूहिक झुंड हाथियों को परेशान करता है और यह उन्हें वापसचले जाने के लिए मजबूर करता है। हाथी, जो सबसे बुद्धिमान जानवर होते हैं और लंबे समय तक अपनी याददाश्त में इन बातों को बनाए रखते हैं, वे सभी उन जगहों पर लौटने से बचते हैं जहां उन्होंने मधुमक्खियों का सामना किया होता है।" श्री सक्सेना ने यह भी कहा कि"प्रोजेक्ट री-हैब का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह हाथियों को कोई नुकसान पहुंचाए बिना ही उन्हें वापस लौटने को मजबूर करता है। इसके अलावा, यह गड्ढों को खोदने या बाड़को खड़ा करने जैसे कई अन्य उपायों की तुलना में बेहद प्रभावी है।

भारत में हाथी के हमलों के कारण हर साल लगभग 500 लोग मारे जाते हैं।यह देश भर में बड़ी बिल्लियों की वजह से हुए घातक हमलों से लगभग 10 गुना अधिक है। 2015 से 2020 तक, हाथियों के हमलों में लगभग 2500 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इसमेंसे अकेले कर्नाटक में लगभग 170 मानवीय मौतें हुई हैं। इसके विपरीत, इस संख्या का लगभगपांचवां हिस्सा, यानी पिछले 5 वर्षों में मनुष्यों द्वारा प्रतिशोध में लगभग 500 हाथियोंकी भी मौत हो चुकी है।

इससे पहले, केवीआईसी की एक इकाई केंद्रीय मधुमक्खी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान पुणे ने हाथियों के हमलों को कम करने के लिए महाराष्ट्र में "मधुमक्खी-बाड़" बनाने के क्षेत्रीय परीक्षण किए थे। हालांकि, यह पहली बार है कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने इस परियोजना को समग्रता में लॉन्च किया है। केवीआईसीने परियोजना के प्रभाव मूल्यांकन के लिए कृषि और बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय, पोन्नमपेटके कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री की सहायता ली है। इस अवसर पर केवीआईसी के मुख्य सलाहकार (रणनीति और सतत विकास) डॉ. आर सुदर्शन और कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री के डीन डॉ. सीजी कुशालप्पा उपस्थितथे।

◆◆◆

..... पृष्ठ सं. 03 के आगे

माननीय प्रधानमंत्री की बांग्लादेश यात्रा के दौरान होने वाले समारोहों की शोभा बढ़ाएगी खादी मुजीब जैकेट

है, वहीं यह बांग्लादेश के युवाओं के बीच तेजी से फैशन की अभिव्यक्ति बनता जा रहा है। इसी प्रकार, भारत की वस्त्र धरोहर खादी, परम्परा और फैशन का एक खास मिश्रण है। खादी से बनी मुजीब जैकेट ने समारोह के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मूल्यों में खासी बढ़ोतरी की।" उन्होंने कहा कि इससे खादी को वैश्विक और राजनयिक मंच पर व्यापक प्रोत्साहन भी मिलेगा।

राजनयिक कन्साइनमेंट को पहले ही ढाका के लिए रवाना कर दिया गया था। जैकेट के राजनयिक उद्देश्यों को देखते हुए, केवीआईसी ने इसे काफी प्राथमिकता दी थी और समय से पहले इसकी आपूर्ति कर दी गई।

★★★

श्री नितिन गडकरी द्वारा स्फूर्ति योजना के तहत क्लस्टर्स स्थापित करने हेतु कार्यशाला का उद्घाटन

नई दिल्ली, 09 मार्च, 2021: केन्द्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री श्री नितिन गडकरी ने स्फूर्ति योजना (पारंपरिक उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए राशि देने की योजना) के तहत पारंपरिक शिल्पकारों के लिए क्लस्टर स्थापित करने हेतु एक दो दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। यह कार्यशाला नई दिल्ली स्थित डॉ. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र में आयोजित की गई है।

इस अवसर पर एमएसएमई राज्य मंत्री श्री प्रताप चन्द्र सारंगी भी उपस्थित थे। श्री गडकरी ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यशाला का उद्घाटन किया। इस कार्यशाला का उद्देश्य हितधारकों को समयबद्ध तरीके से क्लस्टर्स बनाने की योजना तैयार करने के संबंध में प्रशिक्षित करना है ताकि सरकार के प्रयासों का लाभ जल्दी-से-जल्दी लाभार्थियों को मिल सके, उनकी उत्पादन गुणवत्ता बढ़ सके और उनकी आय में इजाफा हो सके। अनुमान है कि स्फूर्ति योजना से संबद्ध करीब 400 संगठन इस दो दिन की कार्यशाला में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अथवा स्वयं उपस्थित होकर भाग लेंगे। इस कार्यशाला में स्फूर्ति क्लस्टर्स के सफलतापूर्वक लागू किए जाने के संबंध में कुछ केस स्टडीज पर भी चर्चा होगी।

इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री गडकरी ने स्फूर्ति के तहत 5,000 क्लस्टर्स बनाने का लक्ष्य तय किया। इस समय ऐसे 394 स्वीकृत क्लस्टर्स हैं। उन्होंने कहा कि "इस व्यवस्था को डिजिटलाइज किया जाए तथा समयबद्ध, नतीजा देने वाली, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जाए "। उन्होंने कहा कि देश के सकल घरेलू उत्पादन में एमएसएमई क्षेत्र का योगदान बढ़ाकर 40 प्रतिशत किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि एमएसएमई क्षेत्र ने अब तक देश में 11 करोड़ लोगों को नौकरियां प्रदान की हैं। उन्होंने एमएसएमई मंत्रालय की इस बात के लिए प्रशंसा की कि उसने तीन माह की समयावधि तय कर आवेदनों की छंटनी और मंजूरी/नामंजूरी दिया जाना तय किया। उन्होंने कहा कि किसी भी कार्य में विलंब किए जाने के तौर-तरीकों को अब छोड़ देना होगा। श्री गडकरी ने " हितधारकों के बीच समुचित सहयोग, सहकार और संपर्क कायम करने पर जोर दिया।"

श्री गडकरी ने इस बात पर जोर दिया कि "हर जिले में खादी ग्रामोद्योग और ग्रामीण उद्योगों की एक न एक शाखा जरूर होनी चाहिए और इनका कारोबार मौजूदा 88,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 5 लाख करोड़ रुपये तक ले जाया जाना चाहिए।" उन्होंने कहा कि "सभी योजनाओं का आकलन इस आधार पर किया जाना चाहिए कि उन्होंने कितने रोजगार अवसर पैदा किए और कितने लोगों के जीवनस्तर में सुधार किया।"

इस अवसर पर अपने संबोधन में एमएसएमई राज्य मंत्री श्री प्रताप चन्द्र सारंगी ने कहा कि "आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देश को प्रतिस्पर्धात्मक गति को आत्मसात करना होगा।' उन्होंने कहा कि "हर गांव में ऐसे क्लस्टर्स स्थापित किए जाने चाहिए और सभी संबद्ध एजेंसियों की इच्छा शक्ति और तकनीकी उन्नति इसे संभव बना सकती है "। उन्होंने कहा कि "हमें राष्ट्र प्रथम की भावना रखते हुए ऐसी दीर्घकालिक प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल करना चाहिए जिनसे हर किसी को लाभ हो।"

आज की तारीख तक स्फूर्ति योजना के तहत 394 क्लस्टर्स को मंजूरी दी जा चुकी है जिनमें से 93 कामकाज कर रहे हैं और भारत सरकार की 970.28 करोड़ रुपये की सहायता से 2.34 लाख लाभार्थियों को मदद कर रहे हैं। इस योजना के तहत जिन क्षेत्रों में काम किया जाता है उनमें हस्तशिल्प, हथकरघा, खादी, वस्त्र, कॉयर (नारियल का रेशा), बांस, कृषि प्रसंस्करण, शहद आदि शामिल हैं। •••

केवीआईसी ने हनी मिशन के तहत कूर्ग में कर्नाटक की 100 साल पुरानी हनी गतिविधियों को पुनर्जीवित किया

स्वतंत्रता-पूर्व काल से, मधुमक्खीपालन गतिविधियां कूर्ग के सुरम्य परिदृश्य में पोन्नमपेटमें स्थानीय संस्कृति का एक हिस्सा थी, जिसे अब कर्नाटक में कोडगु के नाम से जाना जाता है। लेकिन बिना किसी भी वैज्ञानिक ज्ञान के कारण, इसे अपरिष्कृत तरीके से अभ्यस्त किया गया था।

हालांकि, 1920 के दशक में, श्री रामकृष्ण शारदा आश्रम के स्वामी शंभवानंद जी ने मधुमक्खी के बक्से की शुरुआत की और वैज्ञानिक रूप से मधुमक्खी पालन गतिविधियों के साथ स्थानीय आबादी को जोड़ा। उन्होंने स्थानीय मधुमक्खी पालकों को देश भर में अपना शहद बेचने के लिए मार्गदर्शन व सहायता भी प्रदान की। स्वामी शंभवानंद जी की एक महिला शिष्या द्वारा मधुमक्खी के बक्से को पहली बार अमेरिका से लाया गया था। बाद में, 1934 में, महात्मा गांधी ने पोन्नमपेट का दौरा किया और गाँव की उद्योग गतिविधियों के एक भाग के रूप में मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहित किया।

उचित तकनीकी और विपणन सहायता की कमी के कारण, कूर्ग क्षेत्र में मधुमक्खीपालन गतिविधियों में तेज गिरावट देखी गई। हालांकि, इस समृद्ध विरासत को आगे बढ़ाने और स्थानीय मधुमक्खीपालकों को सशक्त बनाने की मांग देखते हुए, खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने एक व्यापक योजना बनायी है।

केवीआईसीके अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने हनी मिशन के तहत 50 प्रशिक्षित स्थानीय किसानों को 500

मधुमक्खी के बक्से वितरित किए। यहमधुमक्खी के बक्से वानिकी कॉलेज, पोन्नमपेट में वितरित किए गए थे। पिछले दो वर्षों के दौरान, केवीआईसी ने पहले ही स्थानीय मधुमक्खी पालकों और किसानों को 1250 मधुमक्खी बक्से वितरित किए हैं। फीडबैक और मधुमक्खी पालन के प्रति स्थानीय लोगों के बढ़ते झुकाव से उत्साहित, केवीआईसी अपनी स्फूर्तियोजना के तहत एक शहद क्लस्टर स्थापित करने की प्रक्रिया में है, जो 700 से अधिक स्थानीय किसानों को लाभान्वित करेगा।

कर्नाटक- केरल सीमा पर स्थित, कोडगु क्षेत्र को पश्चिमी घाट की समृद्ध जैव विविधता में रखा गया है। घने जंगलों और कॉफी बागान से घिरा यह क्षेत्र लगभग एक शून्य कीटनाशक क्षेत्र है। कई प्रकार के जंगली खाद्य फल जैसे सेबस्टेन प्लम, ड्रैगन आई फ्रूट, जैक फ्रूट, वाइल्ड ऑलिव, कलस्टर फिग और मेडागास्कर प्लम और भारतीय मसाले जैसे इलायची, काली मिर्च और अन्यमसाले भी इस क्षेत्र में उगाए जाते हैं और यहाँ उत्पादित शहद में समृद्ध औषधीय मूल्य होते हैं।

" केवीआईसी मधुमक्खी पालकों को सशक्त बनाने और उन्हें एक विपणन मंच प्रदान के लिए स्फूर्ति योजना के तहत शहद क्लस्टर की स्थापना के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस योजना के तहत, क्लस्टर स्थापित करने के लिए आवश्यक निधि का 90% सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है, जबकि केवल 10% धनराशि कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा वहन की जाती है। श्री सक्सेना ने कहा कि यह क्लस्टर कोडागु जिले में मधुमक्खी पालन गतिविधियों को और अधिक बढ़ावा देगा, जहां केवीआईसी ने मधुमक्खियों का उपयोग करके मानव - हाथी संघर्षों को कम करने के लिए अनोखा प्रोजेक्ट रि-हैब लॉन्च किया है।

प्रस्तावित शहद क्लस्टर "कोडगू बज़िंग बी हनी क्लस्टर" को कोडागु के कृषि विज्ञान मंच द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इस क्षेत्र का समृद्ध वनस्पति उच्च गुणवत्ता वाले शहद के उत्पादन के लिए अनुकूल है। क्लस्टर मधुमक्खी पालकों और कारीगरों को एक सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) और शहद की बिक्री के लिए निष्कर्षण, बॉटलिंग और पैकेजिंग जैसे अन्य तकनीकी समर्थन प्रदान करेगा।

◆◆◆

..... शेष पृष्ठ सं.4 के आगे

कोविड महामारी के बावजूद, केवीआईसी ने पीएमईजीपी के तहत अब तक का उच्चतम रोज़गार सृजन किया;

की स्वीकृति लिए पीएमईजीपी दिशा-निर्देशों में संशोधन किया और परियोजनाओं के अनुमोदन के लिए केवीआईसी के राज्य निदेशकों को अधिकृत किया, जिससे आवेदनों के निष्पादन में काफी तेजी आई।

केवीआईसी ने अपनी ओर से आवेदनों के समयबद्ध निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए दो बड़े फैसले लिए। पहले चरण में, केवीआईसी ने अपने राज्य निदेशकों द्वारा बैंकों को आवेदनों की जांच और अग्रेषण की समय सीमा घटाकर 90 दिन से सिर्फ 26 दिन कर दी। इसके अलावा, बैंकों के साथ मासिक समन्वय बैठकें विभिन्न स्तरों पर शुरू की गईं, जिसके परिणामस्वरूप लाभार्थियों को ऋणों का समय पर वितरण होने लगा।

◆◆◆

केवीआईसी के ऑनलाइन बिक्री पोर्टल ने नई ऊंचाइयों को छुआ; स्वदेशी को अधिक बढ़ावा

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2021: खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने ऑनलाइन विपणन खंड में प्रवेश कर बड़ी तेजी से देश लोगों के बीच अपनी पहुंच स्थापित की है। खादी के ई- पोर्टल www.khadiindia.gov.in ने अपनी शुरुआत के महज 8 महीनों में ही 1.12 करोड़ रुपये से अधिक का सकल कारोबार किया है।

7 जुलाई 2020 को लॉन्च होने के बाद खादी ई-पोर्टल ने अब तक इस पर आने वाले 65,000 लोगों में से 10,000 से अधिक ग्राहकों द्वारा ऑर्डर किया गया सामान पहुंचाया है। केवीआईसी ने इन ग्राहकों को 1 लाख से अधिक वस्तुएं / चीज़ें वितरित की हैं। इस अवधि के दौरान, औसत ऑनलाइन खरीद 11,000 रुपये प्रति ग्राहक दर्ज की गई है जो खादी की लगातार बढ़ती लोकप्रियता और खरीदारों के सभी वर्गों के लिए इसकी उत्पाद श्रृंखला की विविधता का संकेत है।

केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने खादी के सफल ई-कॉमर्स उद्यम की सराहना करते हुए कहा कि इससे खादी और ग्रामीण उद्योग के उत्पादों की पहुंच एक बड़ी आबादी तक सुलभ कराने के लिए इसे एक व्यापक विपणन मंच प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा, खादी की ई-मार्केटिंग गेम-चेंजर साबित हो रही है। श्री गडकरी ने कहा, प्रति वर्ष 200 करोड़ रुपये के कारोबार तक पहुंचने का प्रयास किया जाना चाहिए।

केवीआईसी ने वेब-डेवलपमेंट पर एक भी रुपया खर्च किए बिना ही ई-पोर्टल को इन-हाउस विकसित किया है। यह एक अन्य कारक है जो खादी ई-पोर्टल को अन्य ई-कॉमर्स साइटों से अलग करता है - अन्य ऑनलाइन पोर्टलों के विपरीत केवीआईसी कैटलॉग, उत्पाद फोटोशूट जैसे सभी लॉजिस्टिक्स और बुनियादी ढांचे का विशेष ख्याल रखता है। साथ ही यह ऑनलाइन इन्वेंट्री बनाए रखता है और ग्राहकों के दरवाजे तक सामान की ढुलाई तथा परिवहन का विशेष ध्यान रखता है। यह खादी कारीगरों, संस्थानों और पीएमईजीपी इकाइयों को खादी उत्पादों को किसी भी वित्तीय बोझ से बचाता है।

माननीय एम.एस.एम. ई. मंत्री श्री नितिन गडकरी ने 8 मार्च 2021 को इंडिया एस एम ई फोरम, मुंबई द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम "शक्ति"-सशक्त महिला उद्यमी 2021 को संबोधित किया। एम एस एम ई राज्य मंत्री श्री प्रताप चंद्र सारंगी और खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने भी कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इस अवसर पर महिला उद्यमियों को सम्मानित किया गया।

महाराष्ट्र के पालघर जिला की पीएमईजीपी उद्यमी को माननीय मंत्री एमएसएमई द्वारा पुरस्कृत किया गया ।

बांस उद्योग में 30,000 करोड़ रुपए तक बढ़ने की क्षमता:

एमएसएमई मंत्री ने बांस के अधिक से अधिक इस्तेमाल की अपील ताकि इसकी मांग और इसके रोपण को बढ़ाया जा सके

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2021:सड़क परिवहन और राजमार्ग और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री श्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बांस प्रौद्योगिकी, उत्पाद और सेवाओं पर एक वर्चुअल प्रदर्शनी को संबोधित किया। प्रदर्शनी का आयोजन इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी (आईएफजीई) द्वारा किया गया।

अपने संबोधन में श्री गडकरी ने कहा कि बाँस की माँग बढ़ाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि कोयले के विकल्प के रूप में बांस का उपयोग करने की क्षमता है और इसका उपयोग निर्माण कार्यों में भी किया जा सकता है।

श्री गडकरी ने कहा कि जल्द ही सभी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की सड़कों के लिए जूट और कॉयर मैट्रेसेज का उपयोग अनिवार्य किया जाएगा। उन्होंने जूट, कॉयर और बांस जैसी पारंपरिक सामग्रियों के और अधिक विकास की वकालत की।

श्री गडकरी ने उम्मीद जताई कि सभी हितधारकों के एकीकृत प्रयासों से भारत में बांस उद्योग 25-30 हजार करोड़ रुपये का हो जाएगा। सैद्धांतिक रूप से सिद्ध, लागत प्रभावी और आकर्षक उत्पाद डिजाइनों से बांस का उपयोग और इसकी मांग बढ़ सकती है जिससे लोगों को बांस रोपण का भी प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने बांस को बढ़ावा देने से संबंधित किसी भी योजना के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से सभी सहायता का आश्वासन दिया।

मंत्री ने कहा कि हमें उत्पाद विकास, बाजार समर्थन के लिए अधिक शोध, अधिक उपयुक्त दृष्टिकोण की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी कहा कि वह बांस और बांस के डंडे के लिए रेलवे से 50 फीसदी सब्सिडी लेने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि बांस के उपयोग और आवश्यकता को बढ़ाने से इसके रोपण में वृद्धि होगी।

उन्होंने कहा कि बांस का इस्तेमाल बायो-सीएनजी और चारकोल बनाने के लिए भी किया जा सकता है और आईआईटी को बांस मिशन के विशेष अनुदानों की मदद से इस पर आगे अनुसंधान करने के लिए शामिल किया जा सकता है।

◆◆◆◆

केंद्रीय एम.एस.एम.ई. मंत्री ने एमएसएमई के प्रौद्योगिकी केंद्रों, विस्तार केंद्रों और उद्यम एक्सप्रेस का उद्घाटन किया

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री नितिन गडकरी ने आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम और मध्य प्रदेश के भोपाल में दो प्रौद्योगिकी केंद्रों, बड़े प्रौद्योगिकी केंद्रों के तीन विस्तार केंद्रों और सात मोबाइल उद्यम एक्सप्रेस का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री गडकरी ने कहा कि अगर देश को गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी की तीन बड़ी समस्याओं से निपटना है तो हमें रोजगारों का सृजन करना होगा।

श्री नितिन गडकरी ने ज्ञान को धन में परिवर्तित करने और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए जिलावार विकास योजना के बारे में जोर दिया। उन्होंने कहा कि तकनीकी केंद्रों को स्थानीय उद्योगों के साथ समन्वय, सहयोग और संचार स्थापित करना चाहिए।

भारतीय युवाओं के लिए अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में मौजूद व्यापक संभावनाओं का जिक्र करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि देश के युवाओं को सफल होने के लिए अवसर, सहायता और उपकरण की जरूरत है। श्री गडकरी ने कहा कि सरकार के सभी विभागों को किसी स्थान का सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य बदलने के लिए समन्वित तरीके से काम करना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि देश में कच्चा माल, युवा और कुशल जनशक्ति के लिए व्यापक संभावनाएं हैं और सरकार सभी उद्यमियों की सहायता करने के लिए तैयार है। हमें आईआईटी, इंजीनियरिंग कॉलेजों और समाज में सफल व्यक्तियों का सहयोग लेने की जरूरत है।

श्री गडकरी ने एकीकृत सोच की जरूरत पर प्रकाश डालते हुए सभी हितधारकों का एक मंच पर आने, मिलकर सोचने और मिलकर काम करने का आह्वान किया। भारतीय ऑटोमोबाइल क्षेत्र का जिक्र करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि हमारा लक्ष्य

अगले पांच वर्षों के दौरान देश के ऑटोमोबाइल उद्योग को मौजूदा साढ़े चार लाख करोड़ रुपये के स्तर से बढ़ाकर दस लाख करोड़ रुपये करने का है।

उन्होंने सभी प्रौद्योगिकी केन्द्रों और विस्तार केन्द्रों के कार्य प्रदर्शन का ऑडिट करने पर जोर दिया। उन्होंने समस्तसंबंधितों से इस प्रणाली को परिणामजनित, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का आह्वान किया।

इस अवसर पर एमएसएमई राज्य मंत्री श्री प्रताप चंद्र सारंगी ने कहा कि इन केन्द्रों में लगभग 2,50,000 छात्र प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और टूल रूम सामान्य डिजाइनिंग से लेकर रोबोटिक्स क्षेत्र का कार्य करता है। मोबाइल उद्यम एक्सप्रेस का जिक्र करते हुए श्री सारंगी ने कहा कि ये मोबाइल वैन गांवों में जाएंगी और लोगों को प्रशिक्षण देने के साथ-साथ उद्यमिता के सभी पहलुओं के बारे में जागरूक बनाएंगी। उन्होंने कहा कि ये वैन लोगों को एमएसएमई के बारे में जानकारी प्रदान करने में मदद करेंगी।

पूरे देश में नए प्रौद्योगिकी केन्द्रों और विस्तार केन्द्रों की स्थापना द्वारा एमएसएमई मंत्रालय का उद्देश्य अधिक से अधिक राज्यों और क्षेत्रों को शामिल करते हुए वर्टिकल के साथ-साथ क्षैतिज विस्तार के साथ भविष्य के लिए तैयार इन नए प्रौद्योगिकी केन्द्रों के माध्यम से प्रौद्योगिकी केन्द्रों के नेटवर्क के भौगोलिक पदचिह्नों को और आगे बढ़ाना है।

यह अनुमान है कि इन नए टीसीएस/ईसीएस केन्द्रों की स्थापना के बाद देश में चार लाख प्रशिक्षुओं और एक लाख एमएसएमई की सहायता करने के लिए अतिरिक्त क्षमता का सृजन होगा, ताकि देश में प्रौद्योगिकी, इनक्यूबेशन, कौशल और परामर्श सहायता उपलब्ध हो और एमएसएमई की प्रतिस्पर्धा में बढ़ोतरी हो, नए एमएसएमई का सृजन हो और देश में नियोजित/बेरोजगार युवाओं की रोजगार क्षमता में बढ़ोतरी हो।

◆◆◆◆

आयोग ने कुम्हार सशक्तिकरण योजना के तहत राजस्थान में 11 जिलों के 1000 कुम्हार परिवारों को सशक्त बनाया

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के रोजगार अभियान को राजस्थान के 1000 प्रशिक्षित कुम्हार परिवारों को 1000 विद्युत चालित कुम्हारी चाक और अन्य मिट्टी के बर्तनों को बनाने के उपकरणों के वितरण के साथ एक बड़ा प्रोत्साहन मिलाहै। केवीआईसी के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने स्थानीय सांसद श्री अर्जुन लाल मीणा की उपस्थिति में उदयपुर में आयोजित एक समारोह में यह उपकरण वितरित किए। केवीआईसी की कुम्हार सशक्तिकरण योजना के तहत प्रशिक्षण, कुम्हार समुदाय के 5000 से अधिक लोगों को रोजगार और स्थायी आजीविका प्रदान करेगा। इस वितरण कार्यक्रम के लाभार्थी जयपुर, उदयपुर, अलवर, दौसा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, टोंक, झालावाड़, भीलवाड़ा और बांसवाड़ा सहित राजस्थान के 11 जिलों में 74 स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के हैं, जो अपने उत्तम मिट्टी के बर्तनों के लिए अत्यधिक प्रशंसित हैं। विद्युत चालित कुम्हारी चाक के अलावा, 100 ब्लेंगर मशीनों को भी वितरित किया गया है।

इन कुम्हारों को खादी और ग्रामोद्योग आयोगद्वारा 10 दिनों का प्रशिक्षण दिया गया है। कुम्हार सशक्तिकरण योजना के 2018 में शुरू होने के बाद से राजस्थान में 1000 विद्युत चालित कुम्हारी चाकों का वितरण इस तरह का सबसे बड़ी प्रकिया है। तब से, जैसलमेर, बाड़मेर, कोटा, जयपुर, दौसा और श्रीगंगानगर जैसे अन्यशहरों के बीच में 3000 से अधिक विद्युत चालित कुम्हारी चाकों का वितरण किया गया है।

केवीआईसीके अध्यक्ष श्री सक्सेना ने कहा कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य हाशिए पर रहने वाले कुम्हार समुदाय को सशक्त बनाना है ताकि उनकी निरंतरता सुनिश्चित हो सके। श्री सक्सेना ने कहा, "कुम्हार समुदाय को सशक्त बनाना, उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ना और मिट्टी के बर्तनों की नष्ट होती कला को पुनर्जीवित करना माननीय प्रधान मंत्री का सपना है, जिसे केवीआईसी द्वारा पुनर्जीवित कर इसे प्रोत्साहित किया जा रहा है।"

राजस्थान में टेराकोटा उत्पादों की समृद्ध विरासत है। लेकिन मिट्टी के बर्तनों की कला वित्तीय अस्थिरता के कारण वर्षों से मरने लगी। कुम्हारों ने काम में अस्थिरता और बाजार सेसमर्थन नहींमिलनेके कारण आजीविका के अन्य स्रोतों की तलाश शुरू कर दी। हालांकि, कुम्हार सशक्तिकरण योजना के तहत, खादी और ग्रामोद्योग आयोगइन कुम्हारों को अपने उत्पाद बेचने और कमाई करने के लिए विपणन मंच प्रदान करता है। राजस्थान के कुम्हार मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे पड़ोसी राज्यों में अपने उत्पाद बेच रहे हैं।

खादी और ग्रामोद्योग आयोगकी पहल पर, "रेल मंत्रालय ने 400 रेलवे स्टेशनों को चिह्नित किया है, जहां यात्रियों को खाने / पेय पदार्थों की सेवा के लिए केवल मिट्टी के बरतन का उपयोग किया जाता है। इनमें राजस्थान के 25 रेलवे स्टेशन जैसे उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, अजमेर और अन्य शामिल हैं। इसने कुम्हारों को एक बड़ा विपणन मंच प्रदान किया है। रेलवे बहुत जल्द 100 अन्य रेलवे स्टेशनों को सूची में शामिल करेगा। केवीआईसी ने पहली बार अपने ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से मिट्टी (दीये) जैसे मिट्टी के अन्य सामानों की

शेष पृष्ठ सं .... 16 पर

वित्तीय सहायता के माध्यम से कुम्हारी उद्योग को सशक्त बनाने हेतु आयोग द्वारा कार्यशाला का आयोजन

खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने मिट्टी के बर्तनों के भारतीय उद्योग को मजबूत करने और हाशिए पर चले गए कुम्हार समुदाय को सशक्त बनाने के लिए वित्तीय सहायता का पता लगाने के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। केवीआईसीके अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना की अध्यक्षता वाली कार्यशाला में बैंकों, माटी कला बोर्ड और कुम्हार (कुम्हार) समुदाय के प्रतिनिधियों सहित विभिन्न हितधारकों ने हिस्सा लिया, जिन्होंने मिट्टी के बर्तनों को स्थायी आजीविका के उपकरण में परिवर्तित करने के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की।

कार्यशाला का उद्देश्य कुम्हारों द्वारा सामना की जा रही उत्पादन और विपणन चुनौतियों पर विशेषज्ञ राय एकत्र करना है। कौशल विकास प्रशिक्षण और आधुनिक मिट्टी के बर्तनों के उपकरण प्रदान करने के अलावा, खादी और ग्रामोद्योग आयोग बर्तनों उद्योग की सहायता करने के लिए बैंक वित्त की खोज भी कर रहा है। जिसके पीछे कुम्हारों को मजबूत करने के लिए एक उद्यमशीलता मॉडल बनाने का सोच है।

इस अवसर पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि आयोग की कुम्हार सशक्तिकरण योजना पहले से ही कुम्हारों के लिए स्थायी आजीविका बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, साथ ही मिट्टी के बर्तनों की विरासत कला का संरक्षण भी कर रही है, जो माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी का सपना है।

हमारे द्वारा किए जा रहे प्रयासों के साथ, केवीआईसीभारतीय कुम्हार उद्यमी बनाने के तरीके तलाश रहा है। केवीआईसी, इन कारीगरों को बैंक वित्त और उन्नत प्रशिक्षण के माध्यम से हैंडहोल्डिंग प्रदान करने के लिए एक तंत्र पर काम कर रहा है जो अंततः उन्हें आत्म निर्भर बना देगा और इस कला के पुनरुद्धार में योगदान देगा। यह विचार कुम्हार सशक्तिकरण योजना द्वारा बनाई गई गति को और बढ़ावा देने के लिए है, जो अब तक कुम्हार समुदाय के 80,000 से अधिक लोगों को लाभान्वित कर चुका है।

कई कुम्हार और उनके प्रतिनिधि - माटी कला विकास प्रकोष्ठ के अध्यक्ष श्री दत्ता प्रजापति, हैदराबाद प्रजापति कुम्हार महासंघ के अध्यक्ष श्री शिवानंद, राजस्थान प्रजापति कुम्हार महासंघ के श्री देवीलाल, माटी कला बोर्ड के उपाध्यक्ष श्री केके प्रजापति वर्मा एवं अन्य लोगों ने कार्यशाला में भाग लिया। कुम्हारों ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कुम्हार समुदाय को सशक्त बनाने के लिए केवीआईसी के प्रयासों के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कुम्हार सशक्तिकरण योजना जैसी रोजगार योजनाओं के लिए केवीआईसी को धन्यवाद दिया जिसके परिणामस्वरूप उनके उत्पादन और आय में कई गुना वृद्धि हुई।

◆◆◆

..... शेष पृष्ठ सं.15 के आगे

आयोग ने कुम्हार सशक्तिकरण योजना के तहत राजस्थान में 11 जिलों के 1000 कुम्हार परिवारों को सशक्त बनाया

बिक्री शुरू की है। इसने इन कुम्हारों को देश के हर हिस्से में अपने उत्पाद बेचने में सक्षम बनाया है।

कुम्हार सशक्तिकरण योजना के तहत, केवीआईसी ने अब तक देश भर में लगभग 25,000 विद्युत चालित कुम्हारी चाकों का वितरण किया है। उन्नत उपकरणों ने मिट्टी के बर्तनों को बनाने में लगने वाले श्रम को लगभग समाप्त कर दिया है और जिससे कुम्हार कारीगरों का कई गुना उत्पादन बढ़ाहै। औसतन, पारंपरिक चाक पर 150-200 कुल्हड़ का दैनिक उत्पादन, इलेक्ट्रिक चाक का उपयोग करके लगभग 800 कुल्हड़ हो गया है। इसके अलावा, आधुनिक उपकरणों का उपयोग करके कुम्हारों की औसत मासिक आय में 3 से 4 गुना की भी वृद्धि हुई है।

●●●●

डीटीसी बस चालकों और परिचालकों को खादी फेस मास्क की आपूर्ति

खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) ने दिल्ली परिवहन निगम (DTC) के ड्राइवरों और कंडक्टरों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले 45,000 खादी फेस मास्क की भारी मात्रा में आपूर्ति की है। KVIC को पिछले महीने दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग से खरीद ऑर्डर मिलने के पश्चात गत सप्ताह मास्क की आपूर्ति की गई।

KVIC ने डबल लेयर्ड कॉटन फेस मास्क की आपूर्ति की है जो सांस लेने योग्य, त्वचा के अनुकूल और लंबे समय तक उपयोग के लिए उपयुक्त हैं। केवीआईसी ने विशेष रूप से इन मास्क के निर्माण के लिए डबल ट्विस्टेड खादी कपड़े का उपयोग किया है क्योंकि यह अंदर से नमी के 70% को बनाए रखने में मदद करता है, जबकि हवा आने के लिए एक आसान मार्ग प्रदान करता है। ये मास्क धोने योग्य और पुन: प्रयोज्य हैं। इन फेस मास्क को मास्क पर छपे डीटीसी लोगो के साथ नीले रंग के कपड़े के संयोजन का उपयोग करके बनाया गया है।

KVIC के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग द्वारा खादी फेस मास्क की थोक खरीद खादी की बढ़ती लोकप्रियता और विभिन्न सरकारी विभागों में खादी की स्वीकार्यता को दर्शाती है। "इस तरह के बड़े आदेश खादी कारीगरों के लिए अतिरिक्त रोजगार पैदा करते हैं। साथ ही, खादी मास्क डीटीसी ड्राइवरों और कंडक्टरों को बीमारी की चपेट में आए लोगों से सुरक्षा प्रदान करेगा।"

गौरतलब है कि पिछले साल अप्रैल में लॉन्च होने के बाद से केवीआईसी ने महज 10 महीनों में 26 लाख से ज्यादा फेस मास्क बेचे हैं। सुविधाजनक और उच्च गुणवत्ता होने के कारण ही खादी और ग्रामोद्योग आयोग को कई थोक ऑर्डर मिले हैं जिसमें इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी से 12.30 लाख मास्क भी शामिल हैं।

हाल ही में, अरुणाचल प्रदेश सरकार ने अपने छात्रों के लिए 1.60 लाख खादी कॉटन फेस मास्क खरीदे थे, जो खादी मास्क की थोक खरीद के लिए जाने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य बन गया। कोविड -19 लॉकडाउन के दौरान, जम्मू और कश्मीर सरकार ने भी 7.50 लाख खादी फेस मास्क खरीदे थे। KVIC को आम जनता के अलावा राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय और विभिन्न केंद्र सरकार के मंत्रालयों और सार्वजनिक उपक्रमों से भी आपूर्ति के दोबारा आदेश मिले हैं।

आयोग मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया

ग्रामोदय, मुंबई, 8 मार्च 2021: कोरोना महामारी के दौरान भी खादी और ग्रामोद्योग की महिला कर्मचारियों के बीच अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का उत्साह पहले जितना ही देखा गया। इस अवसर पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग की मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सुश्री प्रीता वर्मा, वित्तीय सलाहकार सुश्री आशिमा गुप्ता और मुख्य सतर्कता अधिकारी डॉ. संघमित्रा की मौजूदगी में केवीआईसी ने संगठन की महिला कर्मचारियों के लिए एक पुस्तक मेले और केवल महिला कर्मचारियों के लिए रेस्ट रुम का उद्घाटन किया।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अदम्य नारी शक्ति को सलाम करते हुए, केवीआईसी ने कई क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने की दिशा में महिलाओं की कई उपलब्धियों पर गर्व किया। महिला कर्मचारियों ने सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रदर्शन किया, जिसे सभी कर्मचारियों के साथ वेबिनार के माध्यम से डिजिटल रूप से साझा किया गया। केवीआईसी महिला कर्मचारी जो सेवानिवृत्ति होनेको हैं, उन्हें भी इस अवसर पर सम्मानित किया गया।

सी बी कोरा केंद्र बोरिवली

दहानू

भोपाल

देहरादून

आयोग में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया

राज्य कार्यालय, त्रिवेन्द्रम

राज्य कार्यालय, गुवाहाटी

राज्य कार्यालय, लखनऊ

राज्य कार्यालय, त्रिपुरा

हनी मिशन कार्यक्रम के तहत केरल के इडुक्की जिले में मधुमक्खी कालोनियों और उपकरण-किट के साथ 100 बी बक्सेस की आपूर्ति की गयी

वितरण समारोह के दौरान पंचायत अध्यक्ष, वार्ड सदस्य एवं कृषि अधिकारी उपस्थित थे।

आयोग के पीएमटीसी केन्द्र, पंपोर ने उद्यमिता विकास कार्यक्रम के तहत 3 बैच के 76 सफल उम्मीदवारों को प्रमाणपत्र वितरित किए

आयोग के बहु उद्देश्यीय प्रशिक्षण केन्द्र, देहरादून ने 22 मार्च, 2021 को गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज, लक्खीबाग देहरादून में उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में 51 छात्राओं ने भाग लिया।

कुवरपुर, हल्द्वानी में 28.2.2021 को वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन और गुणवत्ता नियंत्रण पर पहले कार्यक्रम का उद्घाटन श्री हरेंद्र सिंह बिष्ट, ग्राम प्रधान ने किया, आयोग के राज्य कार्यालय, देहरादून के तत्वाधान में कुमाऊं मधुमक्खी पालन क्लस्टर द्वारा चैतन्य मौनलय एवं कृषि सेवा समिति के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोग के राज्य कार्यालय, देहरादून के श्री पूर्व कार्यकारी (बीकेआई), बी. डी. कंदपाल और बागवानी विभाग, हल्द्वानी के अधिकारी श्री ब्रजपाल सिंह नेगी भी कार्यक्रम में उपस्थित थे।

डूंगरी, ओखलकांडा में स्फूर्ति योजना के तहत मधुमक्खीपालन पर एक दिवसीय जागरुकता शिविर का आयोजन

कुमाऊ मौनपालन क्लस्टर संचालित संस्था चैतन्य मौनालय एवं कृषि सेवा समिति हल्द्वानी द्वारा ग्राम डूंगरी ओखलकांडा में 02 मार्च, 2021 को स्फूर्ति योजना के तहत मधुमक्खीपालन पर एक दिवसीय जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आयोग के बहु उद्देश्यीय प्रशिक्षण केन्द्र, हल्द्वानी के सह निदेशक श्री इंद्रजीत, राजकीय मौनपालन केंद्र, ज्योलिकोट के वरिष्ठ अनुसंधान सहायक श्री पी. एस. कनवाल एवं मौनपालन विशेषज्ञ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के श्री ब्रजपाल सिंह नेगी एवं ग्राम के अन्य प्रतिनिधि कार्यक्रम में शामिल हुए, इस कार्यक्रम में 150 लोगों ने भाग लिया।

प्रयागराज माघ मेला में राज्य स्तरीय खादी प्रदर्शनी का आयोजन

आयोग के मण्डलीय कार्यालय, वाराणसी द्वारा 10.02.2021 से 01.03.2021 तक प्रयागराज माघ मेला में राज्य स्तरीय खादी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जहाँ पीएमईजीपी इकाइयों के साथ 20 राज्यों के 80 खादी संस्थानों ने अपनी विभिन्न प्रकार की उत्कृष्ट खादी और ग्रामोद्योगी उत्पादों के साथ प्रदर्शनी में भाग लिया। प्रदर्शनी के दौरान 450.00 लाख से अधिक, खादी और ग्रामोद्योगी उत्पादों के रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की गयी । प्रदर्शनी के दौरान कोविड-19 महामारी के लिए जारी सुरक्षा उपायों के दिशानिर्देशों को सख्ती से लागू किया गया।

महाराष्ट्र के राज्य मंत्री श्री नवाब मलिक ने 10 मार्च, 2021 को उद्योग भारती, गोंडल का दौरा किया।

आयोग के बहुउद्देश्यीय प्रशिक्षण केन्द्र, दहानू में 23 मार्च, 2021 को नीरा के प्रसंस्करण से गुड़ बनाने पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

हनी मिशन और ग्रामोद्योग विकास योजना के तहत 27 मार्च, 2021 को मंडल कार्यालय, केवीआईसी, गोरखपुर द्वारा 500 हनी मधुमक्खी के बक्से और टूल किट वितरित किए गए।

दिनांक 17.03.2021 को लक्सर जिला-हरिद्वार में बहुउद्देश्यीय प्रशिक्षण केन्द्र खादी ग्रामोधोग आयोग, देहरादून द्वारा एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजित किया गया जिसमें 157 छात्र छात्राओं ने भाग लिया।

चेन्नई में पी.एम.ई.जी.पी. पर बैंकर्स की समीक्षा बैठक

आयोग के राज्य कार्यालय, चेन्नई में 5 मार्च, 2021 को उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पीएमईजीपी श्री एम. राजनबाबू की अध्यक्षता में पीएमईजीपी पर बैंकर्स की समीक्षा बैठक आयोजित हुई।

आयोग के एमडीटीसी कैंपस, देहरादून में दिनांक 08 मार्च, 2021 से 13 मार्च, 2021 तक डॉल्फिन पी.जी. इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल एंड नेचुरल साइंसेज, मदुवाला, देहरादून, (उत्तराखंड) के बीएससी, कृषि (अंतिम वर्ष) के छात्रों के लिए प्रथम बैच में 29 और द्वितीय बैच में 24 महिला / पुरुष (दो चरणों में) को मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें कुल 53 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्राप्त किया।

आयोग के राज्य कार्यालय, देहरादून ने उज्जवल उत्तराखंड 2021 मेले में भाग लिया।

आयोग के बहु उद्देश्यीय प्रशिक्षण केन्द्र, देहरादून ने 01 मार्च, 2021 को मधुमक्खी पालन पर 5 दिनों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया।

आयोग के मण्डलीय कार्यालय, गोरखपुर के अंतर्गत 06 मार्च, 2021 को हनी मिशन पायलट प्रोजेक्ट के तहत तीन स्वयं सहायित समूह (एसएचजी) क्रमशः जिला बहराईच के एक समूह तथा गोंडा के दो समूह हितग्राहियों को मधुमक्खी बॉक्स एवं टूल्स किट का वितरण किया गया। इस अवसर पर कृषि विज्ञान केंद्र, गोपाल ग्रा। गोंडा के कर्मचारी, महाराजी ग्रामोद्योग प्रशिक्षण संस्थान, प्रयागराज के प्रबंधक श्री आलोक कुमार मोर्या, खादी ग्रामोद्योग आयोग के मण्डलीय कार्यालय, गोरखपुर के सहायक निदेशक श्री मुकेश कुमार श्रीवास्तव, कनिष्ठ कार्यकारी (एफबीएए) श्री चितरंजन सेठी व श्री बलराम शर्मा आदि उपस्थित थे।

त्रि-मासिक वस्त्र सिलाई सत्र का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ और आयोग के बहु उद्देश्यीय प्रशिक्षण केन्द्र, त्रिचूर में आयोजित समापन समारोह में सभी प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र प्रदान किए गए।

आयोग, मुख्यालय, मुंबई में हिन्दी कार्यशाला आयोजित

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम २०२०-२१ में निर्धारित लक्ष्यांक को प्राप्त करने के लिए दिनांक ०४ मार्च, २०२१ को मुख्यालय के ढेबर भाई सभागृह में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में वर्ष २०२० के दौरान आयोग, मुख्यालय में नव नियुक्त कर्मचारियों को "सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग" विषय पर व्याख्यान दिया गया। कार्यशाला के शुभारंभ में श्री कृष्ण पाल, सहायक निदेशक (राजभाषा)/प्रभारी (हिन्दी विभाग) ने अतिथि वक्ता श्री विद्या भूषण तिवारी, सेवानिवृत्त सहायक प्रबन्धक, (राजभाषा) न्यू इंडिया लाइफ इन्श्युरेंस, मुंबई का खादी किट देकर स्वागत किया।

श्री कृष्ण पाल ने नव नियुक्त कर्मचारियों को कार्यालय में हिन्दी विभाग का संक्षिप्त परिचय देते हुए प्रत्येक तिमाही में आयोजित होने वाली कार्यशाला के बारे में बताया। उन्होंने उपस्थित कर्मचारियों को राजभाषा हिन्दी में काम करने हेतु प्रोत्साहित करते हुए ज्यादा से ज्यादा सरकारी काम हिन्दी में करने हेतु प्रेरित किया।

कार्यशाला में अतिथि वक्ता श्री विद्या भूषण तिवारी ने हिन्दी का महत्व बताते हुए इसे संपर्क भाषा बताया। उन्होंने उपस्थित कर्मचारियों को राजभाषा के प्रयोग से जुड़ी अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी दी। सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी का प्रयोग करते हुए पत्राचार एवं टिप्पणियों का प्रतिशत बढ़ाने हेतु अत्यंत सरल एवं महत्वपूर्ण सुझाव दिये। कार्यालयीन कामकाज में प्रयोग होने वाले व्याकरण से जुड़ी समस्याओं पर भी प्रकाश डाला।

प्रतिभागियों ने आयोजित कार्यशाला को अत्यंत उपयोगी बताया। अंत में श्री विवेक शर्मा, कार्यकारी (ग्रामोद्योग) ने अतिथि वक्ता एवं उपस्थित कर्मचारियों को धन्यवाद दिया।

◆◆◆

आयोग के राज्य कार्यालय, भोपाल द्वारा दिनांक 18 को हिंदी कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने अपने व्याख्यान दिये।

24 मार्च, 2021 को आयोग के बहु उद्देश्यीय प्रशिक्षण केन्द्र, देहरादून, (उत्तराखंड)में हिंदी प्रगति समीक्षा और यूनिकोड पर कार्यशाला आयोजित की गई।

आयोग के पूर्वोत्तर सदस्य श्री द्वयू तमो की अध्यक्षता में 12.03.2021 को आंचलिक कार्यालय, गुवाहाटी द्वारा पूर्वोत्तर आंचलिक समीक्षा बैठक आयोजित की गयी, जिसमें आयोग के पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी राज्य निदेशकों ने भाग लिया, बैठक में सभी खादी ग्रामोद्योगी कार्यक्रमों पर चर्चा हुई। माननीय सदस्य ने सभी अधिकारियों को सकारात्मक तरीके से काम करने के लिए कहा। उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रभारी, पूर्वोत्तर क्षेत्र डॉ.सुकुमाल देब ने सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया और मेघालय के निदेशक श्री आई. जवाहर ने सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद दिया।

दिनाँक 20.3.2021 को मण्डलीय कार्यालय, गोरखपुर के अन्तर्गत ग्रामोद्योग विकास योजना हनी मिशन कार्यक्रम के तहत पांच दिवसीय प्रशिक्षण, ज़िला बस्ती में सम्पन्न हुआ।

प्रेस कवरेज

KVIC JOINS HANDS WITH ITBP UNDER "AZADI KA AMRUT MAHOTSAV"

गोरबंजारा समाजाच्या विकासासाठी प्रयत्नशील - ना.नितीन गडकरी

बंजारा पारंपारीक ड्रेस मेकींग क्लस्टरच्या सामान्य सुविधा केंद्र संकुलाचे उद्घाटन

। नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । गुरुवार, 4 मार्च 2021 www.delhi.nbt.in

डीटीसी के ड्राइवर-कंडक्टर पहनेंगे खादी के बने मास्क

विस, नई दिल्ली : आने वाले गर्मी के मौसम के दौरान डीटीसी की बसों के ड्राइवरों और कंडक्टरों को कोरोना के खतरे से बचाने के लिए दिल्ली सरकार ने विशेष पहल की है। सरकार ने खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमिशन (KVIC) को एकमुश्त ऑर्डर देकर खादी के बने खास तरह के मास्क बनवाए है। इन मास्कों का रंग डीटीसी कर्मचारियों की वर्दी से मिलता-जुलता है। इन पर डीटीसी का लोगो भी है।

खादी ग्रामोद्योग के अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट विभाग ने खादी के कपड़े से बने 45 हजार फेस मास्क सप्लाई करने का ऑर्डर दिया था। इसके लिए दिल्ली सरकार करीब साढ़े 13 लाख रुपये खर्च कर रही है। 30 हजार मास्क की पहली खेप डिलिवर कर दी गई है। बाकी बचे 15 हजार मास्क भी हफ्ते भर के अंदर सप्लाई कर दिए जाएंगे।

केवीआईसी के चेयरमैन विनय कुमार सक्सेना ने बताया कि कॉटन के कपड़े से बने डबल लेयर वाले इन फेस मास्क की खासियत यह है कि गर्मी के मौसम के दौरान इन्हें पहनने पर घुटन महसूस नहीं होगी। ये लंबे समय तक इस्तेमाल के लायक है।

FOREVER NEWS

You played "Narad" to block Reliance-Future deal: FMCG distributors to Bezos

New indicative board and signage facilities at Chhatrapati Shivaji Maharaj

DTC Drivers and Conductors to Sport Khadi Face Masks

ಆನೆ ಹಾವಳಿ ತಡೆಗೆ ಜೇನು ನೊಣಗಳ ಬಳಕೆ

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ

प्रेस कवरेज

KVIC joins hands with ITBP under "Azadi ka Amrut Mahotsav.

- Farooq Rather.
- HT CORRESPONDENT.

Jammu March 14: Khadi and Village Industries Commission (KVIC) on Saturday joined hands with ITBP under Azadi ka Amrut Mahotsav by starting a training programme of pottery at Gram Rakh Badoi Jammu to the traditional potters people of the area.

On the Occasion Shri Anil Kumar Sharma, Principal/ Assistant Director, PMTC, KVIC Pampore, 52 Battalion Assistant Commandant, Besides large No. of people were present.

This 10 days training programme for potters is conducted by training centre of KVIC namely PMTC, KVIC, Pampore.

It is worth to mention here that this initiative was taken by the Commandant 52 Battalion Shri Narendra Singh.

Addressing the gathering Shri Anil Kumar Sharma highlighted the various programmes / schemes of KVIC through which the people can be benefited.

Shri Anil emphasised on the traditional arts which are dying due to no interest shown by the people. He requested the people to come forward and help KVIC to restore the traditional arts of J&K.

Shri Anil said that Relationship between KVIC and ITBP is not new. KVIC has already started big Swadeshi drive in ITBP. KVIC has already signed MOU with ITBP for supply of 1.72 lakh cotton Durries every year.

Earlier KVIC had signed an agreement with ITBP for supplying Kacchu Ghani mustard oil.

In the meantime same two training courses on pottery were inaugurated by State Director KVIC, J&K Shri S.P. Khandelwal at Haripur patal Hiranagar Kathua and handle Check Chhan Lal Din Marheen Kathua.

On the Occasion S.P. Khandelwal said that KVIC is going to impart 10 days training to the potters and after that Selp help Groups (SHG's) will be created for the benefit of these potters.

Pertainly, Seventy-five weeks ahead of 75th Independence Day, Prime Minister Narendra Modi recently launched the 'Azadi ka Amrut Mahotsav'. The Mahotsav is being launched on March 12 to commemorate 91 years of Dandi March.

'Azadi ka Amrut Mahotsav' is a series of events organized by the government of India to commemorate the 75th anniversary of Independence. The mahotsav will be celebrated as a peoples' movement across the country.

गोरबंजारा समाजाच्या विकासासाठी प्रयत्नशील - ना.नितीन गडकरी

बंजारा पारंपारीक ड्रेस मेकींग क्लस्टरच्या सामान्य सुविधा केंद्र संकुलाचे उद्घाटन

बीड- गोर बंजारा समाजातील महिलांच्या उन्नतीसाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील असून त्या अनुषंगाने ठोस पाऊले उचलत असल्याची ग्वाही केंद्रिय मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिली.

भारत सरकारच्या सुक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग मंत्रालय, खादी व ग्रामोद्योग संस्था यांच्या मार्फत राबविण्यात येणाऱ्या 'स्फूर्ती' योजनेंतर्गत अंबाजोगाई,बीड येथील हल्याची गोरबंजारा महिला कला विकास मंडळाच्या वतीने राबविण्यात येणाऱ्या बंजारा पारंपारीक ड्रेस मेकींग क्लस्टरच्या सामान्य सुविधा केंद्र संकुलाचे उद्घाटन केंद्रिय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याहस्ते झाले.

या प्रसंगी प्रतापचंद्र षडंगी, खा.प्रितम मुंडे, आ.प्रकाश सोळंके, [illegible] जिल्हाधिकारी रविंद्र [illegible] यांच्या उपस्थितीत २२ फेब्रुवारीला या संकुलाचे उद्घाटन झाले. यावेळी मान्यवर उपस्थित होते. हा प्रकल्प विकसित करण्यात नोडल अधिकारी शिवानंद टाईम इंस्टट्यूट कोल्हापुरचे मुख्यकार्यकारी संचालक राजेंद्र बेंद्रीकर शिंदे यांचे महत्त्वपूर्ण योगदान लाभले. [illegible] महिला कलाविकास मंडळाचे अध्यक्ष [illegible] यांनी यासाठी पाठपुरावा करून गोरबंजारा समाजातील सुमारे २५० महिलांना क्लस्टरच्या माध्यमातून सक्षम बनविण्यासाठी व रोजगाराची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. गणपती पवार यांचे ही या उपक्रमात मोलाचे योगदान आहे. सुक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग मंत्रालयामार्फत या क्लस्टरमधील कारागिरांसाठी कौशल्य प्रशिक्षण अभ्यासक्रम, यंत्र सामुग्री, सामान्य सुविधा केंद्र, खेळते भांडवल आदींसाठी एक कोटी पंधरा लाख रुपयांचा भरीव निधी उपलब्ध करून दिला असून त्या समाजातील महिला व नागरिकांच्या विकासासाठी केंद्र सरकार कटीबद्ध असल्याचे गडकरी म्हणाले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक राजेंद्र बेंद्रीकर शिंदे यांनी केले तर शिवानंद यांनी आभार मानले.

KVIC president Vinaykumar Saxena distributes honey bee colonies to a trainee during a programme held at the College of Forestry in Ponnampet.

KVIC launches RE-HAB pilot project in Kodagu

PONNAMPET, DHNS

Khadi and Village Industries Commission (KVIC) has launched research project RE-HAB (Reducing Elephant Human Attack by using Bees) in Kodagu district.

KVIC president Vinaykumar Saxena inaugurated the RE-HAB pilot project at the College of Forestry in Ponnampet.

The project aims at controlling the human-elephant conflict. In the first phase, beehives were placed in the Nanacchi area on Sunday.

Depending on the success of the project, it can be extended to West Bengal, Chhattisgarh and Assam.

On average, 500 people are attacked by the elephants in Karnataka in a year.

KVIC deputy CEP Satyanarayana Shukla said that under the RE-HAB project, both man and elephant can be saved. It will also help in maintaining a balance in nature, along with the conservation of biodiversity.

Apiculture is not for business alone. It will help in increasing the production in agriculture. Along with honey, farmers can sell bee wax to supplement their income, he added.

College of Forestry head Dr Cheppudira G Kushalappa also spoke on the occasion.

The programme commenced with offering floral tribute to a portrait of Mahatma Gandhi.

KVIC president Vinaykumar also visited the apiculture, bamboo resource centre, GIS lab and forest nursery at the college.

Honey bee colonies were distributed to the beekeeping trainees trained under the Honey Mission of KVIC.

प्रेस कवरेज

15th March-2021

कागज के बने उत्पाद के जरिए मिलेंगे रोजगार

एक समूह में 10 लोग होंगे शामिल, मशीन लगाने को मिलेगा अनुदान

संवाद न्यूज एजेंसी

90 प्रतिशत तक मिलेगा अनुदान

निशुल्क मिलेगा प्रशिक्षण

News | FOREVER NEWS | 26 Feb. 4 March 2021 | 3

Gadkari inaugurates 50 SFURTI clusters in 18 States for supporting traditional craft artisans

New Delhi: Gadkari inaugurates 50 SFURTI clusters in 18 States for supporting traditional craft artisans. Union Minister for MSME & Road Transport & Highways, Shri Nitin Gadkari this evening inaugurated 50 artisan-based SFURTI clusters, spread over 18 States. In the 50 clusters inaugurated today, over 42,000 artisans have been supported in the traditional segments of muslin, khadi, coir, handicraft, handlooms, woodcraft, leather, pottery, carpet weaving, bamboo, agro-processing, tea, etc. The Ministry of MSME, Govt. of India has funded an amount of around Rs.85 crore for the development of these 50 clusters. The Ministry of MSME is implementing a Scheme of Fund for Regeneration of Traditional Industries (SFURTI) with a view to organize traditional industries and artisans into clusters to make them competitive and increase their income.

Gadkari inaugurates 50 SFURTI clusters in 18 States for supporting traditional craft artisans. Inaugurating the clusters, Shri Gadkari said more research needs to be done on what kind of village products are required by the consumers, and how to attractively design and market these products. He suggested that the National Institute of Design, Ahmedabad may be approached to improve the design and attractiveness of traditional products. A web portal is also required, on the lines of Amazon or Alibaba, to market these products effectively, both in India and abroad, he added. www.forevernews.in

Pitting David against Goliath

Kodagu to have 'bee fences' to ward off wild elephants

K. KRISHNA KUMAR
MYSURU

Pitting the largest animal on land against a minute insect. That is how the authorities intend to mitigate human-elephant conflict that seems to continue unabated in Kodagu and other parts of south Karnataka region.

A pilot project launched in Kodagu entails installing bee boxes along the periphery of the forest and the villages with the belief that the elephants will not venture anywhere close to the bees and thus avoid transgressing into human landscape. This idea stems from the elephants' proven fear of the bees.

An initiative of the Khadi and Village Industries Commission (KVIC), Project RE-HAB (Reducing Elephant-Human Attacks using Bees) intends to create "bee fences" to thwart elephant attacks in human habitations using honeybees.

Bee boxes installed across the elephant paths by the KVIC as part of Project Re-Hab in Kodagu. SPECIAL ARRANGEMENT

The pilot project was launched at four locations around Chelur village in Kodagu district by KVIC chairman Vinai Kumar Saxena on Monday.

These spots are located on the periphery of Nagarahole National Park and Tiger Reserve, known conflict zones.

The total cost of the project is ₹15 lakh and Project RE-HAB is a sub-mission of KVIC's National Honey Mission.

KVIC has set up 11 to 15 interspersed bee boxes at each of the four locations. The bee boxes are set up in the passage ways of human-elephant conflict zones to block the entrance of elephants to human habitations.

The boxes are connected with a string so that when elephants attempt to pass through, a tug causes the bees to swarm the elephant herds and dissuade them from progressing further.

Bee boxes have been placed on the ground as well as hung from the trees. High resolution, night vision cameras have been installed at strategic points to record the impact of bees on elephants and their behaviour in these zones.

The biggest advantage of Project RE-HAB is that it dissuades elephants without causing any harm to them. Besides being extremely cost-effective as compared to various other measures such as digging trenches or erecting fences, according to Mr. Saxena.

Between 2015 and 2020, nearly 2,500 people have lost their lives in elephant attacks across India. Out of which about 170 human fatalities have been reported in Karnataka alone, according to KVIC.

KVIC has roped in the College of Forestry under the University of Agriculture and Horticultural Sciences, Ponnampet, for impact assessment of the project.

ग्रामीण जनजागृती शिबिरात मार्गदर्शन करताना विजय मोरे शेजारी मान्यवर.(छाया-अनिल वीर)

महाबळेश्वर तालुक्यात ग्रामीण जनजागृती शिबिर संपन्न

महाबळेश्वर/प्रतिनिधी :- महाबळेश्वर तालुक्यातील बिरमणि, हटलोट व घोगलवाडी येथे ग्रामीण जनजागृती शिबिर संपन्न झाले. खादी ग्रामोद्योग आयोग भारत सरकार, सी. बी. कोरा ग्रामोद्योग संस्थान बोरिवली मुंबई, माऊली बहुउद्देशीय प्रशिक्षण विकास संस्था व घाडगे एज्युकेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने ग्रामीण जनजागृती शिबिर ग्रामपंचायत बिरमणी, हतलोट आणि घोगलवाडी या ठिकाणी कोरोना'च्या पार्श्वभूमीवर सर्व नियम पाळून आयोजित करण्यात आले होते.

सदर कार्यक्रमास प्रमुख पाहुणे खादी आणि ग्रामोद्योग सी.बी. कोरा बोरिवली'चे संचालक प्राचार्य असद मलिक,खादी आणि ग्रामोद्योग मार्फत उमाकांत डोईफोडे आणि जि. के. असोलकर, दीपक बोर्डे (कृषी अधिकारी महाबळेश्वर),धैर्यशील गायकवाड (ग्रामसेवक), व रोहन निगडे(कृषी सहाय्यक) या मान्यवरांनी उपस्थित राहून शेतीला जोडधंदा, मध उत्पादन, लघु उद्योग प्रशिक्षण व शासनाच्या विविध योजनांची परिपूर्ण माहिती दिली.

यावेळी आयोजक माऊली बहुउद्देशीय प्रशिक्षण आणि विकास संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष विजय भाऊराव घाडगे यांनी या पुढे नवनवीन उद्योग निर्मिती साठी ग्रामस्थांना सहकार्य करण्यासाठी आश्वासीत केले.सदरच्या कार्यक्रमास ग्रामस्थ उपस्थित होते.

प्रेस कवरेज

KVIC joins hands with ITBP under "Azadi ka Amrut Mahotsav"

FAROOQ RATHER
RAJOURI, MAR 14 :

Khadi and Village Industries Commission (KVIC) on Saturday joined hands with ITBP under Azadi ka Amrut Mahotsav by starting a training programme of pottery at Gram Rakh Badoi Jammu to the traditional potters people of the area.

On the Occasion Shri Anil Kumar Sharma, Principal/Assistant Director, PMTC, KVIC Pampore, 52 Battalion Assistant Commandant, Besides large No. of people were present.

This 10 days training programme for potters is conducted by training centre of KVIC namely PMTC, KVIC, Pampore.

It is worth to mention here that this initiative was taken by the Commandant 52 Battalion Shri Narendra Singh.

Addressing the gathering Shri Anil Kumar Sharma highlighted the various programmes / schemes of KVIC through which the people can be benefited.

Shri Anil emphasised on the traditional arts which are dying due to no interest shown by the people. He requested the people to come forward and help KVIC to restore the traditional arts of J&K.

Shri Anil said that Relationship between KVIC and ITBP is not new. KVIC has already started big Swadeshi drive in ITBP. KVIC has already signed MOU with ITBP for supply of 1.72 lakh cotton Durries every year.

Earlier KVIC had signed an agreement with ITBP for supplying Kacchi Ghani mustard oil.

In the meantime same two training courses on pottery were inaugurated by State Director KVIC, J&K Shri S.P. Khandelwal at Haripur patal Hiranagar Kathua and handle Check Chhan Lal Din Marheen Kathua.

On the Occasion S.P. Khandelwal said that KVIC is going to impart 10 days training to the potters and after that Selp help Groups (SHG's) will be created for the benefit of these potters.

Pertainly, Seventy-five weeks ahead of 75th Independence Day, Prime Minister Narendra Modi recently launched the 'Azadi ka Amrut Mahotsav'. The Mahotsav is being launched on March 12 to commemorate 91 years of Dandi March.

'Azadi ka Amrut Mahotsav' is a series of events organized by the government of India to commemorate the 75th anniversary of Independence. The mahotsav will be celebrated as a peoples' movement across the country.

KVIC celebrates International Women's Day

By Chandrashekhar Hendve

The zeal to celebrate the International women's Day among women employees of Khadi and Village Industries women during Pandemic was as high as ever. On this occasion, Preeta Verma, Chief Executive Officer, KVIC in the presence of Ms. Ashima Gupta, Financial Advisor and Dr. Sanghamitra, Chief Vigilance Officer KVIC inaugurated a book fair and a new ladies' room for women employees of the Organisation.

Saluting the indomitable Nari Shakti on International Women's Day, KVIC took pride in the many accomplishments of the women towards furthering women empowerment across a wide range of sectors. The women employees performed cultural activities which were digitally shared through webinar with all the employees. The KVIC women employees who are due for retirement on superannuation were also felicitated on the occasion.

प्रेस कवरेज

KVIC's RE-HAB project to prevent elephant-human conflict using bees

The pilot project has been launched in Karnataka

OUR CORRESPONDENT

NEW DELHI: Khadi and Village Industries Commission (KVIC) on Monday launched a unique project of creating "bee-fences" to mitigate human-elephant conflicts in the country, but it's a reality as the initiative has been taken to reduce elephant-human attacks using bees. The pilot project RE-HAB, which has been launched in Karnataka, is a sub-mission of KVIC's National Honey Mission and bee boxes have been used as a fence to prevent the attack of elephants.

The project that will cost just Rs 15 lakh launched at four locations around village Chelur in Kodagu district of Karnataka by KVIC Chairman Vinai Kumar Saxena. These spots are located on the periphery of Nagarhole National Park and Tiger Reserve and are known to be human-elephant conflict zones.

KVIC has set up 15-20 interspersed bee boxes at each of the four locations and these bees boxes are set up in the passageways of elephant-human conflict zones to block the entrance of elephants to human habitations.

Commenting on the initiative, KVIC chairman Saxena said, "This unique initiative has been taken as a sustainable resolution to the human-elephant conflicts that are common in several parts of the country."

"It has been scientifically recorded that elephants are annoyed and even frightened of honey bees. Elephants fear that the bee swarms can bite their sensitive inner side of the trunk and eyes. The collective buzz of the bees is annoying to elephants that force them to return. Elephants, who are the most intelligent animal and carry their memories for long, avoid returning to the place where they have encountered honey bees," Saxena said.

"The biggest advantage of project RE-HAB is that it dissuades elephants without causing any harm to them. Besides, it is extremely cost-effective as compared to various other measures like digging trenches or erecting fences," Saxena added.

"The boxes are connected with a string so that when elephants attempt to pass through, a tug or pull causes the bees to swarm the elephant herds and dissuade them from progressing further. Bee boxes have been placed on the ground as well as hung from the trees to block the passageway of elephants," the KVIC said in a statement.

It further added that high resolution, night vision cameras have also been installed at strategic points to record the impact of bees on elephants and their behaviour in these zones.

Nearly 500 people die every year due to elephant attacks in India, which is nearly 10 times more than the fatalities caused by big cats across the country.

Notably, nearly 2,500 people have lost their lives in elephant attacks between 2015 to 2020 and of these deaths, nearly 170 human fatalities have been reported in Karnataka alone.

बंजारा पारंपारिक ड्रेस मेकींग क्लस्टरच्या सामान्य सुविधा केंद्र संकुलाचे उद्घाटन

बीड । वार्ताहर

[illegible]

[illegible]

सोशल मीडिया पर केवीआईसी

-फेसबुक पर

सोशल मीडिया पर केवीआईसी

इन्स्टाग्राम पर

• Special Day posts •